GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1237
TO BE ANSWERED ON THE 3RD MARCH, 2015

PRODUCTION OF OIL PALM

1237. SHRI KIRTI AZAD:
SHRI DUSHYANT CHAUTALA:
SHRI B.V. NAIK:

Will the Minister of AGRICULTURE कृषि मंत्री
be pleased to state:

(a) the production of oil palm in the country during each of the last three years and the current year, State-wise;

(b) whether the Government has set any target regarding production of oil palm in the country during the 12th Five Year Plan period, if so, the details and the present status thereof;

(c) whether the Government proposes to fix procurement price for oil palm in view of its plummeting market price over the months, if so, the details thereof;

(d) whether any requests/representations have been received from States for inclusion of oil palm in the list of crops getting Minimum Support Price, if so, the details thereof and the action taken by the Government thereon; and

(e) the measures taken/being taken by the Government increase the production of oil palm in order to reduce the dependence on import of palm oil in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI MOHANBHAI KUNDARIA)

(a): The State-wise details of production of crude palm oil (CPO) during each of the last three years are given in Annexure.

(b): No targets have been fixed for production of crude palm oil during 12th Five Year Plan. However, it is targeted to bring an additional area of 1.25 lakhs hectare under oil palm cultivation during 12th Five Year Plan. During the first two years from 2012-13 to 2013-14 of 12th Five Year Plan, 49,248 hectare area has been brought under oil palm cultivation.

(c): Oil palm is covered under Market Intervention Scheme (MIS), which is implemented by Ministry of Agriculture on the request of the State Governments, for procurement of perishable agricultural and horticultural commodities in the event of fall in market prices. Government of India has recommended a formula for pricing of Fresh Fruit Bunches (FFBs) of oil palm to the State Governments.

(d): No such representations have been received in last two years.

(e): In order to promote cultivation of oil palm, Government of India has launched the National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) in 2014-15 in the country.

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1237
3 मार्च, 2015 को उत्तरार्थ

विषय: पाम तेल का उत्पादन

1237 श्री कीर्ति आजादः
श्री दुष्यंत चौटालाः
श्री बी.बी. नाईकः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में पाम तेल के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पाम तेल के उत्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकार का पाम तेल के कई महीनों से नीचे गिर रहे बाजार-मूल्य के मद्देनज़र इसका क्रय मूल्य निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों की ओर से पाम तेल को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कर रही फसलों की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पाम तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) प्रत्येक अंतिम तीन वर्षों के दौरान कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पाम ऑयल की खेती के अंतर्गत 1.25 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात 2012-13 से 2013-14 के दौरान पाम ऑयल की खेती के तहत 49,248 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया है।

(ग) ऑयल पाम को मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के तहत कवर किया जाता है, जिसे मण्डी मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में शीघ्र खराब होने वाले कृषि तथा बागवानी उत्पादों की खरीद हेतु राज्य सरकारों के अनुरोध पर कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऑयल पाम के ताजे फल समूह (एफएफबी) के मूल्य निर्धारण हेतु एक नियम की सिफारिश की है।

(घ) विगत दो वर्षों में ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने देश में 2014-15 में राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) की शुरूआत की है।

Annexure

Annexure to Question No. 1237 for answer on 03.03.2015.

State-wise production of crude palm oil (CPO)

Sl.No.	States	Production of CPO(MT)		
		2011-12	2012-13	2013-14
1.	Andhra Pradesh	97987.00	127569.91	161566.47
2.	Karnataka	1739.59	1770.00	1736.00
3.	Tamil Nadu	758.80	1035.05	820.35
4.	Gujarat	0.00	0.00	0.00
5.	Orissa	2162.00	442.96	558.07
6.	Goa	394.45	371.93	370.60
7.	Kerala	7500.00	7378.00	6303.00
8.	Mizoram	0.00	0.00	0.00
	Total	110541.84	138567.85	171354.49

****

अ० प्र० सं० 1237

अनुबंध

कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) का राज्य-वार उत्पादन

क्र.सं.	राज्य	सीपीओ का उत्पादन (मीट्रिक टन)		
		2011-12	2012-13	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश	97987.00	127569.91	161566.47
2.	कर्नाटक	1739.59	1770.00	1736.00
3.	तमिलनाडु	758.80	1035.05	820.35
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
5.	उड़ीसा	2162.00	442.96	558.07
6.	गोवा	394.45	371.93	370.60
7.	केरल	7500.00	7378.00	6303.00
8.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
	कुल	**110541.84**	**138567.85**	**171354.49**

xxxxxxxx